



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 पौष, 1940 (श०)

संख्या- 75 राँची, शुक्रवार,

25 जनवरी, 2019 (ई०)

---

#### राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

-----  
संकल्प

22 जनवरी, 2019

**विषय :-** राज्य की सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने के संबंध में।

संचिका संख्या-5/स.भू. विविध (सबलीज)-134/18-293/रा०,-- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 17 जनवरी, 2019 के मद संख्या-07 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में राज्य की सरकारी भूमि के लीज बंदोबस्ती में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित करने के संबंध में निम्नरूपेण प्रावधान किया जाता है :-

(I) खासमहाल मैन्युअल के Rule 16, 17, 19 एवं 20 में सबलीज के प्रावधान को सन्निहित किया जाता है तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के संकल्प संख्या-4306, दिनांक 24 अक्टूबर, 2014 की कंडिका-4 (d) एवं (e) को निम्नरूपेण प्रतिस्थापित किया जाता है:-

(d) लीज पर दी गई राज्य की सरकारी भूमि पर लीजधारक द्वारा सरकार की अनुमति प्राप्त कर किसी अन्य के पक्ष में सबलीज करने की कार्रवाई की जा सकेगी, जो लीज पर दी गयी भूमि की शर्त से आच्छादित होगी। सबलीज की अवधि भूमि की लीज अवधि के अंतर्गत होगी तथा उसके नवीकरण

की अवधि भूमि की लीज की विस्तारित अवधि से आच्छादित होगी। सबलीज के दर एवं अन्य शर्तों का निर्धारण कर राज्य सरकार द्वारा इसे अलग से अधिसूचित किया जायेगा।

(e) लीज बन्दोबस्त की गई राज्य सरकार की भूमि अहस्तानांतरणीय होगी परन्तु इसका सबलीज किया जा सकेगा, जिसका निबंधन कराया जाना अनिवार्य होगा। लीज/सबलीज भूमि प्रतिभूति के रूप में बैंक या किसी वित्तीय संस्थाओं में बंधक के रूप में नहीं रखी जा सकेगी।

(II) भू-अर्जन अधिनियम के तहत अर्जित भूमि का सबलीज करने के लिए **Deed of Conveyance** में उल्लेखित शर्तों के अधीन सबलीज की जा सकेगी।

(III) राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निःशुल्क/टोकन राशि पर लीज बंदोबस्त की गई राज्य की सरकारी भूमि को राज्य सरकार की अनुमति से ही सबलीज किया जा सकेगा।

कमलेश्वर प्रसाद सिंह,  
सरकार के संयुक्त सचिव।

-----